सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हरला

बनाम

राजस्थान का राज्य

[मेहर चंद महाजन और विवियन बोस जेजे]

जयपुर विधि अधिनियम, 1923 की सं. 3 (ख)-जयपुर अफीम अधिनियम, 1923-विधि मंत्रिपरिषद द्वारा पारित जो राजपत्र में घोषित या प्रकाशित नहीं किया गया-कानून की वैधता-कानूनों की घोषणा की आवश्यकता-प्राकृतिक न्याय।

प्राकृतिक न्याय के लिए आवश्यक है कि इससे पहले कि कोई कानून लागू हो सके, इसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसे कुछ पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी पुरुषों को पता चल सके कि यह क्या है।; या कम से कम कुछ विशेष नियम या विनियमन या प्रथागत चैनल होना चाहिए जिसके माध्यम से या उसके माध्यम से इस तरह के ज्ञान को उचित और उचित परिश्रम के अभ्यास के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

जयपुर राज्य की सरकार और प्रशासन के लिए क्राउन प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद ने 1923 में जयपुर अफीम अधिनियम नामक एक कानून बनाने का इरादा रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इस कानून को न तो प्रख्यापित किया गया या राजपत्र में प्रकाशित किया गया और न ही जनता को बताया गया।. जयपुर विधि अधिनियम, 1923, जिसे परिषद द्वारा भी पारित किया गया था और जो 1 नवंबर, 1924 को लागू हुआ था, धारा 3 (बी) द्वारा प्रदान किया गया था कि जयपुर राज्य के न्यायालय द्वारा प्रशासित किया जाने वाला कानून होगा। (ख) उक्त प्रदेशों के भीतर अब लागू सभी विनियम और वे अधिनियमन और विनियम जो इसके बाद राज्य द्वारा समय-समय पर पारित किए जा सकते हैं और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जा सकते हैं। 1938 में जयपुर अफीम अधिनियम में इस आशय का एक खंड जोड़कर संशोधन किया गया कि "यह 1 सितंबर, 1924 से लागू होगा।

यह माना गया कि कानून के आगे प्रकाशन या घोषणा के बिना परिषद के संकल्प का पारित होना कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं था और जयपुर अफीम अधिनियम इसलिए एक वैध कानून नहीं था। आगे कहा गया कि उक्त अधिनियम को जयपुर विधि अधिनियम 1923 की धारा 3 (बी) द्वारा बचाया नहीं गया था, क्योंकि यह 1 नवंबर, 1924 को लागू एक वैध कानून नहीं था, और 1938 में केवल एक खंड जोड़ने का कोई फायदा नहीं था कि यह 1924 में लागू होगा।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1951 की आपराधिक अपील सं. 5 सांबत 2005 की आपराधिक संदर्भ संख्या 229 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 18 अगस्त, 1950 के निर्णय और आदेश (नवल किशोर सी. जे. और दवे जे.) से अपील।

अपीलार्थी के लिए एच. जे. उमरीगर।

प्रत्यर्थी के लिए जी. सी. माथुर।

1951 में। 24 सितंबर कोर्ट का निर्णय दिया गया था

बोस जे.-अपीलकर्ता को जयपुर अफीम अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया।. इस तरह का मामला मामूली है, लेकिन जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी क्योंकि अधिनियम की वैधता को छूने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु उठता है।. हम तथ्यों को कालानुक्रमिक रूप से बताएंगे।

यह स्वीकार किया जाता है कि जयपुर के शासकों के पास कानून सहित सरकार की पूर्ण शक्तियां थीं।. 7 सितंबर, 1922 को स्वर्गीय महाराजा की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के समय उनके उत्तराधिकारी, वर्तमान महाराजा, नाबालिग थे। तदनुसार, क्राउन प्रतिनिधि ने महाराजा के अल्पमत के दौरान राज्य की सरकार और प्रशासन की देखभाल के लिए मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की।

11 दिसंबर, 1923 को महाराजा के अल्पमत के दौरान, इस परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जो जयपुर को अधिनियमित करने के लिए था।

अफीम अधिनियम, और एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या इस अधिनियम को जनता को अवगत कराने के लिए राजपत्र या अन्य माध्यमों के बिना संकल्प का पारित होना ही इसे कानून बनाने के लिए पर्याप्त था। हमारी राय है कि ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा करने के अपने कारणों को बताने से पहले, हम कुछ और तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

लगभग एक ही समय में (कहने का मतलब है, वर्ष 1923 - हमें सटीक तारीख नहीं दी गई है) उसी परिषद ने जयपुर विधि अधिनियम, 1923 अधिनियमित किया। इस अधिनियम की धारा 3 (बी) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

"3. शासक के विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जयपुर राज्य के न्यायालय द्वारा प्रशासित किया जाने वाला कानून निम्नानुसार होगा:

(ख) उक्त क्षेत्रों में अब लागू सभी विनियम और उसके बाद राज्य द्वारा समय-समय पर पारित किए जाने वाले और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले अधिनियमन और विनियम."

यह कानून 1 नवंबर, 1924 को लागू हुआ। यह स्वीकार किया जाता है कि जयपुर अफीम अधिनियम 1 नवंबर, 1924 से पहले या बाद में राजपत्र में कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि यह था

यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह पहले से ही एक "विनियमन" था उस तारीख को लागू।

परिणाम का एकमात्र अन्य तथ्य यह है कि 19 मई, 1938 को जयपुर अफीम अधिनियम की धारा 1 को उपधारा (सी) को जोड़कर संशोधित किया गया था जो निम्नानुसार था:

(सी) यह 1 सितम्बर, 1924 से लागू होगा।

वह अपराध जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था यह 8 अक्टूबर, 1948 को हुआ था।

इनमें से अंतिम अधिनियम, अर्थात् 19 मई, 1938 के अधिनियम के बारे में सबसे पहले बात करते हुए, हम इसे एक तरफ रख सकते हैं क्योंकि जब तक अफीम अधिनियम बनाए जाने पर वैध नहीं होता, चौदह वर्ष बाद यह कहते हुए कि यह चौदह वर्ष पहले की तारीख से लागू होगा, केवल एक खंड जोड़ना बेकार होगा। वर्ष 1938 में एक कानून था जिसके तहत 1 नवंबर, 1924 के बाद के सभी अधिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। इसलिए, यदि अफीम अधिनियम उस तारीख को एक वैध अधिनियम नहीं था, तो चौदह साल बाद राजपत्र में इसके केवल एक खंड के प्रकाशन से इसे मान्य नहीं किया जा सकता था। 1923 के जयपुर कानून अधिनियम के लिए पूरे अधिनियमन को प्रकाशित करना आवश्यक था; इसलिए केवल एक खंड का प्रकाशन इसे मान्य नहीं करेगा यदि यह पहले से ही मान्य नहीं था। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किसी कानून को पूर्वगामी बनाया जा सकता है ताकि 1938 में प्रकाशन द्वारा 1924 से प्रभावी किया जा सके, हालांकि उस बिंदु पर तर्क दिया गया था। यह हमें 1923 की स्थिति में वापस लाता है और सवाल उठाता है कि क्या जयपुर परिषद के केवल एक प्रस्ताव द्वारा एक कानून लागू किया जा सकता है।

हम नहीं जानते कि जयपुर में किसी अधिनियम के लागू होने के संबंध में वहां कौन से कानून लागू थे। हमें कोई नहीं दिखाया गया, न ही हमारा ध्यान किसी भी प्रथा की ओर आकर्षित

किया गया जिसे मामले को नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। किसी विशेष कानून या रिवाज के अभाव में, हमारा विचार है कि किसी राज्य के विषयों को उन कानूनों द्वारा दंडित या दंडित करने की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जिनके बारे में वे उचित परिश्रम के अभ्यास के साथ भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक है

इससे पहले कि कोई कानून लागू हो सके, इसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसे कुछ पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी पुरुषों को पता चल सके कि यह क्या है; या, कम से कम, कुछ विशेष नियम या विनियमन या प्रथागत चैनल होना चाहिए जिसके माध्यम से या उसके माध्यम से उचित और उचित परिश्रम के अभ्यास के साथ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह विचार कि एक ऐसे कक्ष के गुप्त अवकाश में लिया गया निर्णय, जिस तक जनता की कोई पहुंच नहीं है और जिस तक उनके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की भी कोई पहुंच नहीं है और जिसके बारे में वे सामान्य रूप से कुछ भी नहीं जान सकते हैं, फिर भी बिना किसी और चीज के एक प्रस्ताव पारित करके उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित कर सकता है। यह उसकी अंतरात्मा को झकझोर देता है। इसलिए किसी भी कानून, नियम, विनियमन या रिवाज के अभाव में, हम मानते हैं कि एक कानून इस तरह से अस्तित्व में नहीं आ सकता है। किसी उचित प्रकार की घोषणा या प्रकाशन आवश्यक है।

इंग्लैंड में नियम यह है कि संसद के अधिनियम उस दिन के पहले क्षण से कानून बन जाते हैं जिस दिन उन्हें शाही सहमति प्राप्त होती है लेकिन शाही घोषणाएं केवल तभी होती हैं जब वास्तव में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होती हैं. हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम (हैलशम संस्करण), खंड VI और 32 हैलबरी के इंग्लैंड के नियम (हैलशाम संस्करण), पृष्ठ 150 नोट (आर) के पैराग्राफ 776, पृष्ठ 601 के फ़ुटनोट (ए) देखें।. लेकिन वहां भी संसद के एक विशेष अधिनियम को लागू करना आवश्यक था ताकि ऐसी घोषणाओं को राजपत्र में प्रकाशन द्वारा कानून बनने में सक्षम बनाया जा सके, हालांकि एक शाही उद्घोषणा संसद के अधिनियम के अलावा सर्वोच्च प्रकार का कानून है, जिसे ब्रिटिश संविधान के लिए जाना जाता है; और यहां तक कि लंदन गजट में प्रकाशन स्कॉटलैंड में उद्घोषणा को वैध नहीं बनाएगा और न ही एडिनबर्ग गजट में प्रकाशन इसे इंग्लैंड के लिए वैध बना देगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि केवल शाही उद्घोषणा को लागू करना या उस पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं है। कानून बनने से पहले प्रकाशन होना चाहिए, और इंग्लैंड में प्रकाशन की प्रकृति संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

इस मामले को विनियमित करने वाला संसद का अधिनियम 1877 का क्राउन ऑफिस अधिनियम (40 और 41 विक्टोरिया सीएच 41) है। यह अधिनियम, कतिपय सरकारी राजपत्रों में प्रकाशन का प्रावधान करने के अतिरिक्त,

जनता को उद्घोषणाओं से अवगत कराने के सर्वोत्तम साधनों के लिए परिषद में आदेश द्वारा नियम बनाने का भी प्रावधान करता है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने क्राउन ऑफिस अधिनियम में जोर दिया है कि न केवल राजपत्र में प्रकाशन होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा प्रकाशन के अन्य तरीके भी होने चाहिए, यदि परिषद में आदेश है। निर्देश देता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को पता चल सके कि ये विशेष कानून क्या हैं। क्राउन ऑफिस एक्ट काउंसिल में महामहिम को इन कानूनों को जनता को बताने के सर्वोत्तम तरीके पर विचार करने के लिए सावधानीपूर्वक निर्देशित करता है और उस निकाय को उसी के लिए नियम तैयार करने और उन्हें काउंसिल में एक आदेश में शामिल करने का अधिकार देता है। हम यह मानते हैं कि यदि इन उद्घोषणाओं को इस प्रकार तैयार किए गए नियमों के अनुसार सख्ती से प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो वे वैध कानून नहीं होंगे।

इस प्रश्न के अंतर्निहित सिद्धांत पर इंग्लैंड में न्यायिक रूप से विचार किया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ हद तक निचले स्तर पर, जॉनसन बनाम सरगेंट (') में यह माना गया था कि बीन्स, मटर और पल्स (अनुरोध) आदेश, 1917 के तहत खाद्य नियंत्रक का एक आदेश तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि इसे जनता को नहीं बताया जाता है, और उस तरह के आदेश और ब्रिटिश संसद के अधिनियमों के बीच अंतर पर जोर दिया जाता है। अंतर स्पष्ट है। ब्रिटिश संसद के अधिनियम सार्वजनिक रूप से अधिनियमित किए जाते हैं। बहस जनता के लिए खुली है और अधिनियमों को लोगों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा पारित किया जाता है, जिन्हें सिद्धांत रूप में यह देखने के लिए भरोसा किया जा सकता है कि उनके घटक जानते हैं कि क्या किया गया है। वे अखबारों में और अब वायरलेस पर भी व्यापक प्रचार प्राप्त करते हैं। खाद्य नियंत्रक की ऐसी शाही घोषणाएं और आदेश नहीं हैं।. इसलिए उनके मामलों में घोषणा और प्रकाशन होना चाहिए। प्रकाशन का तरीका भिन्न हो सकता है; जो एक देश में एक अच्छी विधि है, जरूरी नहीं कि दूसरे में सबसे अच्छी हो। लेकिन किसी प्रकार का उचित प्रकाशन होना चाहिए।

न ही यह सिद्धांत इंग्लैंड के लिए अजीब है। यह नेपोलियन संहिता द्वारा फ्रांस पर लागू किया गया था, जिसके पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून "उसके प्रख्यापन के आधार पर" निष्पादित होते हैं और वे होंगे यह "उस क्षण से लागू होता है जब

(1) [1918] 1 के. बी. 101; 67 एल.जे.के.बी. 122.

उनके प्रख्यापन के बारे में जाना जा सकता था। उदाहरण के लिए, भारत के रक्षा नियमों के नियम 119 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में भी इसे भारत में लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, देखें, (क्राउन बनाम मंघुमल टेकुमल (1), शकूर बनाम राजा सम्राट (2) और बाबूलाल बनाम राजा सम्राट (3)। यह सच है कि इनमें से कोई भी मामला हमारे सामने मौजूद मामले के अनुरूप नहीं है, लेकिन वे केवल एक गहरे नियम के विशेष अनुप्रयोग हैं जो प्राकृतिक न्याय पर आधारित है।

जयपुर अफीम अधिनियम पारित करने वाली मंत्रिपरिषद एक संप्रभु निकाय नहीं थी और न ही इसने अपने अधिकार से कार्य किया था। इसे क्राउन प्रतिनिधि द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, और 11 अगस्त, 1923 को जयपुर गजट अधिसूचना ने इसकी शक्तियों को परिभाषित और सीमित कर दिया था। इसलिए हम इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और धारणाओं पर विचार करने के हकदार हैं जो ब्रिटिश संविधान के अधीन हैं, क्योंकि यह अकल्पनीय है कि महामहिम के एक प्रतिनिधि ने विचार किया होगा एक ऐसे निकाय का निर्माण जो प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के लिए इतनी घृणित शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को साझा करते हैं। हम मानते हैं कि, इसके विपरीत कुछ विशिष्ट कानून या रिवाज के अभाव में, जयपुर राज्य में बिना किसी प्रकाशन या घोषणा के मंत्रिपरिषद का केवल एक संकल्प कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

एक अन्य मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है। यह आग्रह किया गया था कि 1923 के जयपुर कानून अधिनियम की धारा 3 (बी) ने राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता से लागू सभी नियमों को बचा लिया। ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिनियम ने केवल उन कानूनों को बचाया जो उस समय वैध थे, न कि उन प्रस्तावों को जिन्होंने कभी कानून का बल हासिल नहीं किया था।.

अपील सफल होती है. दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। जुर्माना अदा करने पर वापस कर दिया जाएगा।

अपील स्वीकृत की जाती है

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः आर. ए. गोविंद

प्रतिवादी के लिए अभिकर्ताः पी. ए. मेहता

(1) आई. एल. आर. 1944 कराची 107। (3) आई. एल. आर. 1945 नाग। 762।

(2) आई. एल. आर. 1944 नाग। 150।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।